Fiscal Policy and Full Employment

1

राजकोषिय नीति का अर्थ सरकार की व्यय, कर, ऋण तथा ऋण के प्रबन्ध से सम्बन्धित उन क्रिया कलापों से है जिनका प्रयोग सरकार उत्पादन, आय, रोजगार, कीमत स्तर तथा आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव लाने व अवांछित प्रभावों को टालने के उद्देश्य से करती है।

Classical economists अवरुद्ध नीति (Laissez faire) के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। अतः अर्थव्यवस्था पूर्णरोजगार की स्थिति पर स्वयमेव पहुंच जाती है व उसमें किसी प्रकार के राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

परन्तु कीन्स तथा लर्नर जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राजकोषिय नीति की प्राचीन विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। कीन्स का मत था कि उन्नत अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग के प्रति रुझान कम हो जाता है और बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अधिक बचत और कम उपभोग की इस प्रवृत्ति का परिणाम यह होता है कि अर्थव्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। इस संतुलन को बनाये रखने के लिए सरकार का दायित्व होता है कि वह सरकारी व्यय में वृद्धि करे। इसप्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा सरकारी व्यय और आय के परिवर्तन कर कुल मांग और पूर्ति के बीच सन्तुलन कायम कर पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सके।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था पूर्णतया विकसित है तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य 'आर्थिक स्थिरता' प्राप्त करना होगा। यदि अल्पविकसित है तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य तीव्र रूप से आर्थिक विकास करना होता है।

Scanned with CamScanner

किसी अल्पविकसित देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि के लिए क्रियात्मक वित्त प्रबन्धन और उसकी व्यवस्था करना है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य अल्पविकसित देशों के लिए न तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के ठोस वित्त के सिद्धान्त के अनुसार 'तटस्थ' होगा जिसमें सरकारी व्यय अनुत्पादक होते हैं और न केन्सवादी स्फीतिक प्रकार का होगा जिसमें निवेश वृद्धि की निरंतरता का अभाव पाया जाता है और न ही हैराड-डोमर के दृष्टिकोण पर आधारित होगा जिसमें अर्थव्यवस्था में विनियोग की बहुत ऊँची दर उपलब्ध होती है।

भारत जैसे अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होते हैं -

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना
To increase Employment opportunity —

भारत जैसे विकासशील देश जो गरीबी के दुश्चक्र में फंसे हुए हैं जहाँ आय, बचत तथा उपभोग का स्तर अत्यन्त ही कम है राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी को रोजगार मिल सके।

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों के वृद्धि के लिए सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पड़ती है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय के दो रूप हो सकते हैं ① समुद्दीपन व्यय (Pump priming Expenditure) तथा ② क्षतिपूरक व्यय (Compensatory Expenditure)। यहाँ समुद्दीपन व्यय का अर्थ है निजी व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकारी व्यय द्वारा गई क्रयशक्ति का सृजन करना तथा क्षतिपूरक व्यय का अर्थ है - निजी मांग की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी बजट में किए गए व्यय में परिवर्तन। इन दोनों राजकोषीय उपायों से निवेश, आय एवं रोजगार स्तरों को ऊंचा बनाने में मदद मिलती है।

केन्स ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निर्माण नीति (Public work Policy)

का समर्थन किया है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों से लोगों के हाथों में क्रयशक्ति पहुँचेगी जिससे उनका उपभोग व्यय बढ़ेगा, बाजार मांग में वृद्धि होगी फलतः उत्पादन एवं रोजगार बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था सुस्ती व मंदी की दशाओं से मुक्त हो जायेगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए केन्स ने लीक रीकिंग (Leaf Raaking) तक का सुझाव दिया। लीक रीकिंग का अर्थ अनुत्पादक कार्यों में सार्वजनिक निवेश से है। जैसे गड्ढे खुदवाना और उन्हें पुनः मिट्टी से भरवाना आदि। इसी तरह सरकार राजकोषीय नीति के अन्य उपकरणों अथवा अस्त्रों जैसे - करारोपण की नीति, सार्वजनिक ऋण नीति आदि के माध्यम से भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि ला सकती है।

2. आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना (To increase Economic Growth Rate)

विकासशील देशों की प्रमुख समस्या होती है देश का तेजी के साथ विकास करना। इसकी पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि दर को बढ़ाना है। सरकार को करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था आदि राजकोषीय उपायों का प्रयोग ऐसे तालमेल के साथ करना चाहिए ताकि उत्पादन, उपभोग तथा वितरण पर इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े बल्कि सम्पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था का इस तरह विकास हो कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हो सके। इसमें आर्थिक विकास की दर जनसंख्या वृद्धि दर से आगे निकल सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह सड़क, परिवहन, विद्युत व शक्ति के साधनों तथा संचार सुविधाएँ सम्बन्धी उद्योगों को बढ़ावा दे। निजी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करे। कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन की नई-नई एवं आधुनिक विधियों की खोज हेतु सुविधाएं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

तथा अन्य विकासपरक सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ जिससे लोगों की कार्य क्षमता बढ़े और उत्पादन व आय में वृद्धि हो सके। और अंततः देश का उच्चस्तरीय आर्थिक विकास हो सके।

3. पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना
(To increase Capital Formation)

अल्पविकसित देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है। इन देशों में पूंजी की कमी पूंजी-निर्माण व पूंजी संचय में बाधक है। प्रो० रेगनर नर्कसे (R. Nurkse) के अनुसार अल्पविकसित देशों की आय का स्तर निम्न बचत व निवेश के स्तर भी निम्न होते हैं फलतः उत्पादन व आय का स्तर निम्न ही बना रहता है। अतः इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत होती है। सरकार अपना हस्तक्षेप राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत करारोपण द्वारा चालू उपभोग को कम करके, सार्वजनिक व्यय द्वारा श्रम को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय को बढ़ाकर बचत में वृद्धि करने के प्रयास किये जाते हैं। इससे पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक बचत राशि को जुटाना सम्भव होता है। इसतरह राजकोषीय नीति के अन्य उपकरण जैसे सरकार द्वारा नए करारोपण पुराने करों की दरों में वृद्धि करना, अनुत्पादक व्ययों में कमी लाकर, सार्वजनिक ऋण लेकर, सार्वजनिक उपक्रमों में अतिरेक प्राप्त कर तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेकर विकास के लिए आवश्यक बचत राशि जुटाने का प्रयास करती है। जिसे उत्पादन कार्य में पूंजी के रूप में निवेश करके अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के उत्पादन व आय को बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक संवृद्धि को तीव्र किया जा सकता है।

4. आय एवं सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना
(To Reduce Inequality of Income and Wealth)

विकासशील देशों में आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति का

Scanned with CamScanner

मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना तथा समाज में आय तथा धन के समान वितरण को स्थापित करना है। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत करों की दरों को अधिक प्रगतिशील बनाकर तथा करों में कई तरह की छूटों को देकर समाज में आय व धन के वितरण को समान बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा सफाई आदि क्षेत्रों पर सरकारी व्यय के द्वारा भी निम्न आय-वर्ग के लोगों का रहन-सहन सुधारा जा सकता है। इस तरह अब यह धारणा स्वीकृत है कि बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक विकास महत्वहीन है।

5. स्फीतिजनक प्रभावों को रोकना (To check the Inflationary Pressures)

अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रा स्फीति के प्रभावों को कम करना भी होता है। इन देशों में जहाँ बढ़े हुए व्ययों को पूरा करने के लिए की वित्त व्यवस्था और उसमें निहित बढ़ी हुई मुद्रा-पूर्ति के साथ मुद्रा-स्फीति की समस्या जुड़ी हुई है वहाँ कीमत स्थायित्व के लिए राजकोषीय नीति का विशेष महत्व है। बजट प्रक्रिया में समायोजन तथा विभिन्न कर नीतियों के आधार पर आय एवं व्यय में समायोजन के साथ घाटे की वित्त व्यवस्था आदि के रूपों में अतिरिक्त साधनों का इस प्रकार प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि मुद्रा स्फीति तथा उसके हानिकारक प्रभावों को रोका जा सके। यह कार्य सरकार अपनी राजकोषीय नीति को लागू करके कर सकती है। वह अनुत्पादक व्ययों को कम करके तथा उपयुक्त कर नीति द्वारा अतिरिक्त साधनों को प्राप्त करके इन देशों के आर्थिक विकास में साधनों की माँग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित कर सकती है।

भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति के इन प्रमुख उद्देश्यों के अलावा कुछ अन्य

उद्देश्य भी हो सकते हैं जैसे-- क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, बचत व निवेश को बढ़ावा देना, विद्यमान संसाधनों को अनुत्पादक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर मोड़ना आदि। इन उद्देश्यों को पूरा करने में राजकोषीय नीति का कार्यात्मक वित्त का दृष्टिकोण सक्रिय वित्त (Activating finance) के रूप में कार्य होगा। Activating finance के अनुसार राजकोषीय नीति का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पूँजी निर्माण के लिए बचतों व संसाधनों को बढ़ाने तथा तीव्र आर्थिक विकास में वृद्धि करें।

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College